



2026:AHC: 55966

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2318/2025

नितिन बंसल

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश कुमार तिवारी, बलराम सिंह, शिव कुमार सिंह
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, मो. फैज़

न्यायालय संख्या- 85

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार सिंह, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. फैज़ और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ द्वारा भरण-पोषण मामला संख्या 1070 वर्ष 2019 (श्रीमती निधि बंसल और एक अन्य बनाम नितिन बंसल), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 12.03.2025 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को प्रार्थना पत्र की तिथि से विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) को 6000/- रुपये प्रति माह और विपक्षी संख्या 3 (नाबालिग पुत्री) को 4000/- रुपये की भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना है कि वह (पुनरीक्षणकर्ता) पहले एक फैक्ट्री में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था, लेकिन उसके विरुद्ध लंबित मुकदमेबाजी के कारण, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। वर्तमान में, उसके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने शेयर बाजार में पैसा निवेश किया था, और पूरा निवेश डूब गया है। अतः, अवर न्यायालय द्वारा प्रदान की गई भरण-पोषण राशि अत्यधिक, बहुत अधिक है, और पुनरीक्षणकर्ता की आय के अनुरूप नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 एक शिक्षित महिला है और सिलाई तथा कढ़ाई के काम में लगी हुई है, जिससे वह पर्याप्त आय अर्जित करती है और अपना तथा अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

4. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, कुल 10,000/- रुपये की भरण-पोषण राशि को अत्यधिक और उसकी क्षमता से परे नहीं कहा जा सकता है।

5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए तथा पत्रावली और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और विपक्षी संख्या 3 उसकी नाबालिग पुत्री है। जहाँ तक विपक्षी संख्या 2 के अलग रहने का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अपना स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता की ओर से की गई उपेक्षा के कारण अलग रह रही है। अभिलेख पर विपक्षी संख्या 2 की आय दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए, वह अपना और अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं और यह न्यायालय एक पुनरीक्षण न्यायालय होने के नाते, अपना स्वयं का निष्कर्ष देने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, जब तक कि न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत और तथ्यों तथा विधि के विरुद्ध न हो।

6. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता की आय का संबंध है, पुनरीक्षणकर्ता फैक्ट्री में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था लेकिन पक्षकारों के बीच कई मामलों में उलझने के कारण, उसने अपनी नौकरी खो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दी है और अब वह बेरोजगार है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर पुनरीक्षणकर्ता की आय दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. चूँकि पुनरीक्षणकर्ता ने किसी शारीरिक विकृति का दावा नहीं किया है, इसलिए यह न्यायालय यह उपधारणा करता है कि पुनरीक्षणकर्ता/पति एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है और इसलिए, वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के अपने पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। 'रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य (2021) 2 एस.सी.सी. 324; कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 2383 और कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी (1970) 3 एस.सी.सी. 129' के मामलों में। 'रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एस.सी.सी. 324 और कुलभूषण कुमार (डॉ.) बनाम राज कुमारी, (1970) 3 एस.सी.सी. 129' में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि भरण-पोषण भत्ते उचित और यथार्थवादी होने चाहिए, और दो चरम सीमाओं में से किसी से भी बचना चाहिए अर्थात् पत्नी को दिया जाने वाला भरण-पोषण न तो इतना खर्चीला होना चाहिए जो प्रत्यर्थी के लिए दमनकारी और असहनीय हो जाए, और न ही यह इतना अल्प होना चाहिए कि यह पत्नी को दरिद्रता की ओर धकेल दे।

8. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, भले ही पुनरीक्षणकर्ता को एक कुशल श्रमिक मान लिया जाए, वह 1000/- रुपये प्रतिदिन कमा सकता है, जो 30,000/- रुपये प्रति माह बनता है और 'रजनेश बनाम नेहा' के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी किया है कि भरण-पोषण भत्ते पति की शुद्ध आय के 25% की सीमा तक प्रदान किए जा सकते हैं, जो 7,500/- रुपये आता है।

9. इस प्रकार, उपरोक्त के दृष्टिगत, न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई कुल 10,000/- रुपये की भरण-पोषण राशि पुनरीक्षणकर्ता की आय के अनुरूप नहीं है। यह सत्य है कि अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना पति का विधिक दायित्व है, लेकिन भरण-पोषण की राशि पति की आय के अनुरूप होनी चाहिए। अतः अवर न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया भरण-पोषण अत्यधिक प्रतीत होता है और संशोधित किए जाने योग्य है, इसलिए इसे कुल 10000/- रुपये प्रति माह से घटाकर 7500/- रुपये किया जाता है। जिसमें से 5000/- रुपये प्रति माह विपक्षी संख्या 2 को और 2500/- रुपये प्रति माह विपक्षी संख्या 3 को प्रार्थना पत्र की तिथि से देय है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

18 मार्च, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”